भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3275
दिनांक 20 मार्च, 2025

भारत के महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार का विस्तार

†3275. एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:
श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) की वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है तथा वर्ष 2025 तक भंडारित कच्चे तेल की मात्रा कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसपीआर क्षमता का विस्तार करने हेतु कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) एसपीआर अवसंरचना के विस्तार में प्रस्तावित सार्वजनिक-निजी भागीदारी की स्थिति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में महत्वपूर्ण कच्चे तेल भंडार में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा इन पहलों से क्या वित्तीय लाभ होंगे;
(ड.) देश में कच्चे तेल के भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(च) क्या सरकार द्वारा राजकोट में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है/की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च) : सरकार ने इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाली कंपनी के माध्यम से स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) सुविधाएं 3 स्थानों अर्थात (i) विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), (ii) मंगलुरु (1.5 एमएमटी) और (iii) पादुर (2.5 एमएमटी) क्षमता पर स्थापित की हैं, जिनकी कच्चे तेल की कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) है। कंदराओं में उपलब्ध कच्चे तेल की मात्रा बाजार दशाओं के आधार पर बदलती रहती है। तथापि, वर्तमान में आईएसपीआरएल के कदराओं में लगभग 3.52 एमएमटी कच्चे तेल का स्टॉक उपलब्ध है।

जुलाई 2021 में, सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर ओडिशा के चंडीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर (2.5 एमएमटी) में 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता के साथ दो अतिरिक्त वाणिज्य-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार और तेल विपणन

कंपनियां (ओएमसीज) समय-समय पर तकनीकी और वाणिज्य व्यवहार्यता के आधार पर भंडारण क्षमता में वृद्धि की संभावना का मूल्यांकन करती हैं। अतिरिक्त पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना करने के लिए नए स्थलों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है।

अप्रैल/मई 2020 में कच्चे तेल के कम मूल्यों का लाभ उठाते हुए, कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को पूरी क्षमता तक भर दिया गया था, जिससे लगभग 5000 करोड़ रुपए की नेशनल बचत हुई।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आईएसपीआरएल को व्यावसायीकरण कार्यों के लिए कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) कार्यक्रम के चरण- I के तहत बनाए गए पेट्रोलियम भंडार के हिस्से का उपयोग करने, भारतीय या विदेशी कंपनियों को कंदराओं की समग्र तेल भंडारण क्षमता के 30% को पट्टे पर देने/किराए पर लेने और साथ ही भारतीय कंपनियों को कंदराओं की समग्र तेल भंडारण क्षमता के 20% की बिक्री/खरीद करने की अनुमति प्रदान की है। कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त आय, जिसे पट्टे पर दिया जाता है, सरकार को वापस कर दी जाती है।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए वर्तमान कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों तक कवर की गई हैं जिसमें 64.5 दिनों की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की भंडारण सुविधाओं की क्षमता शामिल है।

***